

ISSN : 2393-8358

UGC Approved, Journal No. 48416 (IJCR)

Impact Factor : 6.0



Interdisciplinary Journal of Contemporary Research

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 10, No. 6.1

June, 2023

PEER-REVIEWED JOURNAL

▶ माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन डॉ० सुषमा अग्रवाल एवं आशिया खातून	70-72
▶ हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र की उभरती गतिशीलता में भारत की रणनीतिक भूमिका शिवम सिंह एवं डॉ० जयकुमार मिश्र	73-76
▶ An Assessment of Employment and Unemployment Status in Bihar and Jharkhand Dr. Kanchan Singh	77-84
▶ Law Relating Condition and Warranty: An Analysis Mahesh kumar Pandey	85-88
▶ Korean Music and Indian Milieu : A Study of Pluralizing Spaces in Indian Popular Culture Sushmita Pandey	89-93
▶ कैमूर जिला में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन में शिक्षण संस्थाओं का योगदान : एक भौगोलिक अध्ययन अर्चना कुमारी	94-96
▶ विश्वनाथ राम की गोबरहा डॉ० प्रणव कुमार गौरव	97-99
▶ ग्रामीण विकास में समावेशी विकास की भूमिका डॉ० ब्रह्मजीत सिंह	100-102
▶ भारत में G20 सम्मेलन की सामाजिक समीक्षा आदर्श बाला	103-105
▶ Vignettes of Diasporic Consciousness in Monica Ali's <i>In the Kitchen</i> Dr. Shilpa Shukla & Satish Kumar	106-110
▶ रहीम के नीतिपरक दोहों की वैचारिक चेतना डॉ० अरुण प्रसाद रजक	111-112
▶ चीन देश में बौद्ध न्याय का संक्षिप्त विवरण छेतन यङ्कियद्	113-116
▶ मानवाधिकार और बौद्ध धर्म : एक अध्ययन नरेन्द्र कुमार	117-120
▶ प्रवासी भारतीय और भारत सरकार की प्रवासन नीति डॉ० नरेंद्र कुमार सिंह एवं अनूप सिंह कुशवाहा	121-126
▶ भगवतः श्रीरामस्य कुण्डल्यां राजयोगविमर्शः अनुजकुमारचौबे	127-130
▶ मल्हार अंग के प्रमुख राग प्रो० बिरेन्द्रनाथ मिश्र	131-133
▶ भारत-बांग्लादेश संबंध : एक विहंगावलोकन राम प्रकाश	134-136

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र की उभरती गतिशीलता में भारत की रणनीतिक भूमिका

शिवम सिंह

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर

डॉ० जयकुमार मिश्र (शोध निर्देशक)

प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर

हिन्द और प्रशान्त महासागर की बढ़ती अहमियत ने "हिन्द-प्रशान्त" क्षेत्र को एक भू-रणनीतिक आयाम के रूप में नई गति दी है और यही वजह है कि 21 वीं सदी के ज्यादातर समय के लिए हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र वैश्विक राजनीति के स्वरूप को आकार देगा। यह वह क्षेत्र है जहां विश्व की महान शक्तियों के बीच (खास तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य) प्रतिस्पर्धा जारी है। यह वह क्षेत्र है जहां दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी नजर आती हैं। चीन की संदिग्ध नीतियां और आक्रामक विस्तारवादी प्रवृत्तियां जिसके चलते हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र से जुड़े लगभग सभी मुल्कों के हित बाधित हो रहे हैं। उसे देखते हुए अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसी विश्व की सभी प्रमुख शक्तियां हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को अपनी विदेश, रक्षा तथा सुरक्षा नीतियों का केंद्र बना रही हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र की बढ़ती अहमियत को समझा जा सकता है। इसमें दो राय नहीं कि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र वो आधार है जिसके चारों ओर कई मुल्क अपनी नीतियों को फिर से स्थापित करने तथा जोड़ने में लगे हैं।

भारत एक स्वतंत्र तथा मुक्त हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र की हमेशा से वकालत करता रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा आसियान के सभी सदस्यों ने एक साथ यह विचार आगे रखा है कि इस क्षेत्र में भारत को एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। अपने दायरे में भारत, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को एक भौगोलिक और रणनीतिक विस्तार, जिसमें दो महासागर को जोड़ने वाले 10 आसियान देश हैं, के रूप में मानता है। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र को लेकर भारत की अवधारणा में "समावेशिता, खुलापन, आसियान केंद्रीयता और एकता" का सार बसता है। भारत के लिए हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र का भौगोलिक दायरा अफ्रीका के पूर्वी किनारे से लेकर ओसियानिया (अफ्रीका के तट से लेकर जो अमेरिका तक फैला है), जिसके साथ पैसिफिक द्वीप के देश भी जुड़े हैं। भारत इंडो ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए), ईस्ट एशिया समिट, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, आसियान रीजनल फोरम, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (बिम्स्टेक), मेकांग गंगा इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी व्यवस्थाओं में सक्रिय भागीदार रहा है। इसके अतिरिक्त भारत इंडियन नेवल सिम्पोजियम का भी आयोजक है। फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (एफआईपीसी) के जरिए भारत पैसिफिक द्वीप के मुल्कों के साथ भी साझेदारी बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है।¹ हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में इस बदलते हुए संदर्भ और जटिल परिदृश्य में, भारत को अपनी विदेश नीति इस तरह से पुनः अनुकूल बनाने की जरूरत है जिससे वह लंबी अवधि में अपने अहम हितों की रक्षा कर सके और साथ ही वह इस क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए काम कर सके। नतीजतन उसे बहुआयामी रणनीतियां अपनानी होंगी जिसमें इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारक और देश शामिल हों।

वैश्विक राजनीति पर पहले यूरो-अटलांटिक राजनीतिक और सामरिक संवाद का वर्चस्व था। अब वही वर्चस्व एशिया-प्रशान्त या यून कहें कि हिन्द-प्रशान्त का हो गया है क्योंकि भू-आर्थिक रूप से इस क्षेत्र ने वैश्विक राजनीति में प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, क्योंकि अमेरिका के बाद विश्व की चार शीर्ष आर्थिक शक्तियां इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। आर्थिक गतिविधियों के ये महत्वपूर्ण केन्द्र हैं— चीन, जापान, भारत तथा इंडोनेशिया। बहुस्तरीय स्तर पर भी इनमें से ज्यादातर देश विशाल एशियाई समुदाय के निर्माण की दिशा में लगे हुए हैं। इस संदर्भ में, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के गठन का लक्ष्य है मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) के विकास के माध्यम से हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में बड़ा आर्थिक समुदाय बनाना। इस प्रकार इस क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तरों पर आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया की परिकल्पना की जा रही है। इसके अलावा, एससीओ तथा सार्क जैसे अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ आसियान के आर्थिक संबंधों के जरिए क्षेत्रीय गतिविधियों और अंतर-क्षेत्रीय स्तरों पर सहयोग की भी शुरुआत की गई है। इस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देश और संबन्धित शक्तियां आर्थिक गतिविधियों के हब के रूप में हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के निर्माण के इच्छुक हैं जिसका परम लक्ष्य होगा इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को एकीकृत करना।²

इंडो-पैसिफिक का क्षेत्र दुनिया की 65 प्रतिशत आबादी वाला क्षेत्र है, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका योगदान 63 प्रतिशत है तथा विश्व के समुद्री व्यापार का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा

इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र और यहां से दूर कई देशों का आर्थिक हित और भविष्य का विकास विस्तारपूर्वक इंडो-पैसिफिक में जहाजों के चलने की स्वतंत्रता तथा व्यापार के मुक्त प्रवाह से जुड़ा है।

1979 का आर्थिक सुधार चीन में चार दशकों का बेमिसाल आर्थिक विकास लेकर आया। 2021 में चीन की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई जो पिछले साल के मुकाबले 3 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा थी। क्रय शक्ति समता (परचेजिंग पावर पैरिटी) के मामले में चीन 2014 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में 2028 तक अमेरिका के मुकाबले चीन आगे निकल जाएगा। आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में चीन के उदय का नतीजा शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव के रूप में निकला है। इसके परिणाम स्वरूप ये दलील दी जा रही है कि एक चालाक लड़ाके चीन के उदय से निपटना इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा आक्रामक चीन का नतीजा, क्वॉड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद के फिर से शुरू होने तथा त्रिपक्षीय सुरक्षा संधि (ऑकस) के एलान के रूप में निकला है। भारत, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया उभरते हुए शक्ति के केन्द्र हैं और उन्हें इस क्षेत्र में संतुलित करने वाली ताकत के तौर पर देखा जा रहा है।¹

यूक्रेन पर रूस के हमले और उसको लेकर पश्चिमी देशों के जवाब ने हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में सत्ता के संघर्ष में एक और आयाम जोड़ दिया है। विश्व के देशों के मौजूदा विभाजन के दौरान चीन तथा रूस के बीच जो नजदीकी रिश्ते दिखे हैं, उसका भविष्य के लिए गंभीर असर हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है जिसमें चीन का विशाल द्विपक्षीय व्यापार सरप्लस (396.58 अरब अमेरिकी डॉलर) है। अमेरिका के साथ अपने व्यापार सरप्लस को संतुलित करना और रूस के साथ संबंध चीन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यूक्रेन संकट को लेकर सीधे हस्तक्षेप करने में पश्चिमी देशों की झिझक भी चीन का हौसला बढ़ा सकती है। इस भू राजनीतिक माहौल में भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा और अस्थिर पानी में ध्यान लगाकर चलना होगा।

ऐसा लगता है कि चीन ने भारत के साथ व्यवहार में लेन-देन का दृष्टिकोण अपनाया है, खासकर 2021 में चतुष्कोणीय (क्वाड) ढांचे को सक्रिय करने के लिए भारत के अमेरिका, जापान तथा आस्ट्रेलिया में शामिल होने के बाद। हिन्द-प्रशान्त में कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुनिश्चित करने के लिए गठित क्वाड के इससे परे कई हित हैं। मार्च 2021 में पहले शिखर सम्मेलन में बताए गए क्वाड के उद्देश्यों में कोविड-19 महामारी के आर्थिक और स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां, आतंकवाद का मुकाबला और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने जैसे विषय शामिल हैं। क्वाड के अन्य सदस्यों के साथ भारत के हाथ मिलाने से चीन और उसके कुछ पड़ोसियों के बीच थोड़ी चिंता पैदा हुई है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपनाई गई लंबी लॉकडाउन रणनीति के कारण भारत-प्रशान्त क्षेत्र में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी शक्ति प्रक्षेपण को उस समय झटका लगा जब अर्थव्यवस्था को इससे भारी नुकसान हुआ। इसी तरह, एकाधिकार निजी व्यापार होल्डिंग्स पर कार्रवाई के साथ-साथ चीन की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामक मुद्रा के साथ, भारत ने अपनी कूटनीति को भी बढ़ाया है और वियतनाम, इण्डोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान आदि जैसे चीन के पड़ोसियों के साथ दुर्जेय सैन्य संबंध बनाए हैं। एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के देशों के साथ, इसमें सैन्य कूटनीति पर जोर देने के साथ क्वाड प्लस के ढांचे के तहत इन देशों (जापान को छोड़कर) के साथ बातचीत शामिल है। जापान, मलेशिया, इण्डोनेशिया और वियतनाम के साथ भारत नियमित रूप से त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय ढांचे में वायु सेना और नौसेना अभ्यास करने में शामिल रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया सैन्य कूटनीति के उपयोग के बारे में भारत का एक नया लेकिन मजबूत फोकस क्षेत्र प्रतीत होता है। क्वाड, यह दुनिया के सबसे बड़े मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाज पर चीन के दावे और उनके भारी कैच को देखते हुए सामान्य रूप से आईओआर और विशेष रूप से हिन्द-प्रशान्त में पहले से ही नाजुक मत्स्य संसाधनों को कमजोर करने का खतरा है। भारत की लुक ईस्ट नीति चीन के लिए उपयुक्त नहीं थी, जिसके बाद इसने भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसियों तक पहुंच बनाई तथा अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के प्रक्षेपण द्वारा समुद्री सीमा पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। मेगा बीआरआई परियोजना के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, आसान वित्त, आर्थिक और सैन्य समर्थन ने दक्षिण एशिया के गरीब विकासशील देशों को चीन की ओर आकर्षित किया है। भारत बीआरआई परियोजना में शामिल नहीं हुआ क्योंकि सीपीईसी विवादित सीमा के पार बना हुआ है। हालांकि, सीमा पर विवाद ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नियन्त्रित नहीं किया है। निजी और सरकारी स्वामित्व वाली कई चीनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, हालांकि गलबान के

दुस्साहस के बाद संख्या कम हो गई है जब चीन की सेना (पीएलए) द्वारा शांति और स्थिरता के लिए समझौते का उल्लंघन किया गया था।¹

भारतीय-प्रशान्त क्षेत्र में विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र शामिल है। इसका संबंध भारतीय सागर और पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र से भी है। भारतीय प्रशान्त क्षेत्र में सघन जनसंख्या, विशाल जलीय संसाधन, व्यस्ततम सामुद्रिक परिवहन मार्ग तथा विवादास्पद भौगोलिक क्षेत्र है। इसको प्रमुखता तभी से मिली, जब इस क्षेत्र में महाशक्तियों के द्वारा प्रतिस्पर्धा की दौड़ होने लगी। जहां तक चीन का सवाल है, इसके द्वारा दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर तथा भारतीय सागर के सामुद्रिक मार्गों का इस्तेमाल चीन के द्वारा किया गया। मलक्का का जलडमरूमध्य भी एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। सभी को मालूम है कि चीन का समूचा आर्थिक विकास व्यापक रूप से ऊर्जा संसाधनों पर ही निर्भर है। इसके अलावे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा भारत भी इन मार्गों पर व्यापार के लिए निर्भर है। इसीलिए एक नियमबद्ध वैश्विक व्यवस्था की वकालत की गई और क्वाड का गठन हुआ। जिसका लक्ष्य 'फ्री एण्ड ओपेन इंडो पैसिफिक' यानी भारतीय प्रशान्त क्षेत्र को मुक्त एवं स्वतंत्र करो रहा। अमेरिका की भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भागीदारी रही ताकि भारतीय प्रशान्त क्षेत्र में संतुलन कायम रह सके।

जहां तक भारत के सामुद्रिक व्यापार संबंधित कूटनीति का प्रश्न है, भारत ने पूरी तरह से अपना ध्यान पूर्वी एशिया तक नौसेना के विस्तार पर केन्द्रित रखा। हालांकि 'भारतीय-प्रशान्त क्षेत्र' में भी सामुद्रिक मार्गों पर संचार व्यवस्था बदस्तूर कायम रही। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका, संशेल्स और मॉरीशस की यात्रा के दौरान भारत ने अपना ध्यान भारतीय प्रशान्त क्षेत्र की तरफ केन्द्रित किया। इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि संयुक्त विकासशील परियोजनाएं भी चलती रहेंगी ताकि इन देशों के निमित्त त्रिस्तरीय सामुद्रिक सुरक्षा लगातार मजबूत होती रहे।

पूर्वी लद्दाख में व्याप्त तनाव और भारतीय प्रशान्त क्षेत्र में पी0एल0ए0 की नौसेना की हरकतों ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। इसी का मुकाबला करने के लिए भारत के द्वारा पड़ोसी देशों के साथ एक नई रणनीतिक भागीदारी तय करनी पड़ी ताकि पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते में एक नई मजबूती पैदा हो। इसके अलावे भारत की यह भी कोशिश रही है कि द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तर पर नौसैन्य अभ्यास किए जाएं ताकि चीन के बढ़ते अतिक्रमण को रोका जा सके। क्योंकि भारत के अनुसार चीन के अतिक्रमण को न केवल हिन्द महासागर बल्कि दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर तथा ताईवान के जलडमरूमध्य पर भी रोक दिए जाने चाहिए। चीन की यह भी रणनीति रही है कि मलक्का के जलडमरूमध्य में संचार संसाधनों को ध्वस्त किया जाए जो अभी समुद्री व्यापार मार्ग के रूप में जाना जाता था। उसका मानना था कि यदि इस मार्ग में आने-जाने वाली जहाजों पर निगरानी और निरीक्षण किया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा। चीन का मानना है कि मलक्का के जलडमरूमध्य को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया को काबू में रखा जा सके। भारत में अति विकसित नौसेना के बन्दरगाह अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो मलक्का के जलडमरूमध्य के निकट है। अगर इस अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को अवरुद्ध कर दिया गया तो चीन के सामुद्रिक व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए चीन के द्वारा महत्वाकांक्षी 'बी0आर0आई0' परियोजना में भारी निवेश किया जा रहा है। विशेष रूप से 'ग्वादर' बन्दरगाह में भारी निवेश हो रहा है जिसका प्रयोग चीनी जलपोतों के माल ढुलाई और फिर वहां से चीन जाने के संबंध में किया जाएगा।² इन सारी गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मलक्का के जलडमरूमध्य पर चीन की निर्भरता कम होती जाएगी।

भारतीय प्रशान्त क्षेत्र में भारत की विदेशनीति के कुछेक आयाम हैं— जैसे— पड़ोसी देशों के मित्र सरकारों के साथ कार्य करना, पड़ोसी देशों की संख्या में विस्तार करना और विशेष रूप से एशिया-पैसिफिक देशों के साथ पड़ोसी के कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा सारे क्षेत्रों में नौसैन्य सहयोग को विकसित करना। यह प्रक्रिया व्यवहार में ला दी गई है और इसके संबंध में अनौपचारिक रूप से विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय नौसेना के मध्य तालमेल चल रहे हैं। जहां तक भारत के अन्यान्य देशों के साथ मिलजुलकर काम करने की बात है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि भारतीय प्रशान्त क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल विकसित हों। इसके पहले भी भारत देश के द्वारा कूटनीतिक गतिविधियां शुरू की गई थी ताकि पड़ोसी देशों को आपदा एवं निराशा के क्षणों में सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें।

भारत की क्षेत्रीय सामुद्रिक रणनीति खासतौर पर 'भारतीय प्रशान्त क्षेत्र' में रणनीतिक एवं आर्थिक हितों को हासिल करने में हैं। भारत की सामुद्रिक रणनीति के तीन आयाम— राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हैं। भारत के सामुद्रिक हितों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रों के रूप और आकृति भी लगातार बदल रहे हैं तथा भारत की सामुद्रिक गतिविधियों में लगातार विस्तार दिख रहा है। इसलिए भारत की

नौसेना में भी परिवर्तन हो रहे क्योंकि इनकी भूमिकाएं और प्रस्थितियां लगातार परिवर्तन के अनुक्रम में ही हैं। 'इंडियन मेरीटाईम डॉक्ट्राइन (2008)' के आधुनिक संस्करण के अनुसार— भारतीय नौसेना के कार्यक्षेत्र का विस्तार पश्चिम में एडेन की खाड़ी से पूर्व में स्थित मलक्का के जलडमरूमध्य तक फैले हुए हैं। इस प्रकार भारत की नौसेना के कार्यक्षेत्र में समूचा हिन्द महासागर शामिल है। इस नौसेना को हर तरह के अधिन्यास दिए गए हैं जिसमें उच्चस्तरीय युद्ध से लेकर मानवीय सहायता के कार्यक्रम शामिल हैं।

एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन की लगातार वृद्धि और भारत-प्रशान्त क्षेत्र में इसके आधिपत्य को देखते हुए, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के निरन्तर उत्थान और हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में उसके आधिपत्य को देखते हुए, भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध एक अनिवार्यता बन गया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों के दायरे में, बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि चीनी आक्रामकता को रोकने और विवादित भूमि सीमाओं जैसे क्षेत्रों में ग्रे जोन जबरदस्ती को संबोधित करने की क्षमता बढ़ाई जा सके। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि "विभाग पीसीआर (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) की आक्रामकता को रोकने की क्षमता बढ़ाने और हिन्द महासागर क्षेत्र में मुक्त और खुली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ हमारी प्रमुख रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाएगा"।⁶

भारतीय-प्रशान्त क्षेत्र का भारत की सुरक्षा एवं संवृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत इस क्षेत्र का अग्रणी देश है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का कायम रहना भारत के सुरक्षा एवं विकास के लिहाज से काफी अहम है। हिन्द महासागर के भी रणनीतिक एवं आर्थिक मायने हैं, इसीलिए इस क्षेत्र के बाहर की भी ताकतें यहां रुचि लेती रहती हैं। आज के वर्तमान परिवेश में 'भारतीय प्रशान्त क्षेत्र' में चीन की गहरी आर्थिक एवं रणनीतिक दिलचस्पी है। अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं— 'बी0आर0आई' एवं पाकिस्तान के साथ खासमखास रिश्ते, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के साथ रणनीतिक भागीदारी के जरिए चीन इस महासागरीय क्षेत्र में अपनी पैठ बना रहा है। इसलिए चीन की तरफ से भारत को सीधी चुनौती मिल रही है। भारत की भी अपनी निजी और क्षेत्रीय स्तर पर महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सभी के अलावा सामुद्रिक आतंकवाद, प्रकृतिक आपदाएं और वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए भी अतिरिक्त और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत के भी अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की अपनी सीमाएं हैं जिसका क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। भारत को चीन से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चीन के पास बेहतर साधन एवं संसाधन है और इसके पास इतना विस्तृत संजाल है कि इसमें व्यापार, निवेश और संबद्धता का पूरा समावेश है। इस लिहाज से भारत के लिए अपरिहार्य है कि वो नई रक्षात्मक योग्यताएं विकसित करें और परस्पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंध को विकसित करें। इसके साथ ही साथ द्वीपीय देशों के साथ भी बहुपक्षीय सहयोग विकसित करें ताकि 'भारतीय प्रशान्त क्षेत्र' में शांति एवं स्थिरता कायम हो।

संदर्भ सूची :

1. प्रमेश साहा, 7 फरवरी 2022, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र की उभरती गतिशीलता में भारत की भूमिका, <https://www.google.com/amp/s/www.orfonline.org/hindi/research/indias-role-in-the-emerging-dynamics-of-the-indo-pacific/>
2. प्रो. यादव आर.एस., हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र की राजनीति और भारत की विदेश नीति, वर्ल्ड फोकस, प्रशान्त अटलांटिक से हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र तक, वैश्विक राजनीति में परिवर्तन, मई 2017, अंक-62, पृ0-7, बी-49, जोशी कालोनी, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली।
3. AIR Marshal Amit Dev, हिन्द-प्रशान्त: चीन का उदय और इंडो-पैसिफिक पर उसका असर, 30 अप्रैल 2022 <https://www.google.com/amp/s/www.orfonline.org/hindi/research/china-rise-and-the-implications-for-the-indo-pacific/>
4. प्रो. स्नेहलता पांडा, रक्षा कूटनीति और भारत की रूप रेखा, वर्ल्ड फोकस, भारत की रक्षा कूटनीति, मार्च 2023, अंक-132, पृ0-24, संपादक-जी. किशोर बाबू, बी-49, जोशी कालोनी, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली और एस. आर. बी. प्रिंटो पैक, ए-8/1, झीलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली से मुद्रित।
5. The Economic Times, 17 February 2021.
6. डॉ. आलोक कुमार गुप्ता और हनी राज, भारत-यूएसए रक्षा संबंध: एक रणनीतिक रूप से अनिवार्य संबंध, वर्ल्ड फोकस, भारत की रक्षा कूटनीति, मार्च 2023, अंक-132, पृ0-31, संपादक-जी. किशोर बाबू, बी-49, जोशी कालोनी, आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली और एस. आर. बी. प्रिंटो पैक, ए-8/1, झीलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली से मुद्रित।